सऊदी-भारत-पाकिस्तान त्रिकोण

लेखक-मोहम्मद अयूब (प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 फरवरी, 2019

"नई दिल्ली को रियाद को इस्लामाबाद से दूर रखने के बारे में अधिक आशावादी नहीं होना चाहिए।"

नई दिल्ली में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या एमबीएस की यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत यह मान कर बैठा है कि इस यात्रा से सऊदी अरब और भारतीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी, जो वर्ष 2016 में प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की रियाद यात्रा के साथ शुरू हुई थी। इस उत्साह में से कुछ भारत में व्यापार और निवेश के विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सऊदी की दिलचस्पी के बारे में तर्कसंगत गणनाओं पर आधारित है। सऊदी अरामको महाराष्ट्र में रत्नागिरी में एक एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ भागीदारी करने में रुचि रखता है, जो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के साथ 44 बिलियन डॉलर का संयुक्त उद्यम है। सऊदी अरब पहले से ही भारत को तेल के तीन सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है।

हालाँकि, बहुत अधिक उत्साह इच्छाधारी सोच और अस्पष्ट बयानों पर आधारित है। जैसे कि रियाद की घोषणा कि भारत आठ देशों में से एक है, जिसके साथ वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को तेज करना चाहता है। नई दिल्ली का आत्म-भ्रम कि अब कश्मीर पर सऊदी रुख बदल गया है और पाकिस्तान के प्रति उसका झुकाव भारत के अनुसार है, थोड़ी जल्दबाजी प्रतीत होती है।

नई दिल्ली की इस तरह की धारणा एक कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। एमबीएस की यात्रा के दौरान इस्लामाबाद में सऊदी विदेश मंत्री का बयान कि रियाद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को 'कम करने' के लिए प्रतिबद्ध है, इसे भारतीय रुख के समर्थन के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करने के बजाय विवाद में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

प्रमुख कारण

नई दिल्ली को इस बात की आशा नहीं करनी चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में सऊदी-भारतीय संबंध के बढ़ने से रियाद को इस्लामाबाद से दूर रखने में सफलता मिलेगी। इस निष्कर्ष पर जाने के कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि आंतरिक सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी सेना ने एक से अधिक बार सऊदी शासकों के प्रेटोरियन गार्ड के रूप में काम किया है और अपने देश पर एमबीएस की अनिश्चित पकड़ दी है, इसके अलावा इन्हें निकट भविष्य में पाकिस्तानी भाड़े के सैनिकों की सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है।

दूसरा, अफगानिस्तान 1980 के दशक में पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए रणनीतिक अभिसरण का बिंदु रहा है। जब सऊदी ने काबुल में सोवियत संघ और उसकी छद्म सरकार से लड़ने वाली इस्लामी ताकतों को भौतिक सहायता के लिए पाकिस्तान को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और इसके फलस्वरूप तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के कारण तालिबान के संरक्षक के रूप में पाकिस्तान का रणनीतिक मूल्य तेजी से बढ़ा है। सऊदी अरब अफगानिस्तान में ईरानी प्रभाव को रोकने में दिलचस्पी रखता है।

ईरान दृष्टिकोण

ईरान पश्चिम एशिया में सऊदी अरब का प्रमुख विरोधी रहा है। सीरिया से लेकर यमन तक पूरे क्षेत्र में सऊदी-ईरानी प्रतिद्वंद्विता निभाई जा रही है। रियाद पाकिस्तान को एक प्रमुख संपत्ति के रूप में मानता है, जो नवाज शरीफ सरकार द्वारा सऊदी-नीत गठबंधन की ओर से यमन युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को मना करने के बावजूद ईरानी प्रभाव के प्रसार की जांच करने के लिए उपयोग कर सकता है। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा

को सऊदी अनुनय के लिए अधिक उत्तरदायी देखता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान अपनी ओर से एमबीएस को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उत्कृष्ट तालमेल के कारण अमेरिका की ओर से एक मूल्यवान वार्ताकार के रूप में मानता है।

इसके अलावा, ईरान के साथ पाकिस्तान का संबंध, कभी भी आसान नहीं रहा है। हाल ही में हुए सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी हमले के बाद एक नया विवाद गहरा गया, जिसमें 27 क्रांतिकारी गार्ड मारे गए। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी ने 'कुछ क्षेत्रीय और ट्रांस-क्षेत्रीय देशों की जासूसी एजेंसियों' पर उंगली उठाई, जिसका संदर्भ पाकिस्तान और अमेरिका से था। आई. आर.सी.जी. (IRGC) के कमांडर ने कहा, 'पाकिस्तान की सरकार को इन आतंकवादी समूहों को शरण देने की कीमत चुकानी होगी और यह कीमत निस्संदेह बहुत अधिक होगी।'

जैसा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते रहे हैं, इसकी संभावना कई गुणा अधिक बढ़ जाती है कि यह सऊदी की ओर और अधिक तेजी से बढ़ेगा। पाकिस्तान में वहाबीवाद पर आधारित सुन्नी कट्टरपंथ को बढ़ाना, इसे सऊदी अरब का स्वाभाविक वैचारिक सहयोगी और शिया ईरान का वैचारिक दुश्मन भी बनाता है।

राहत पैकेज

सऊदी की आर्थिक दानशीलता पाकिस्तान के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसकी गंभीर आर्थिक स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में उधार मांगने के लिए मजबूर करती है, जिसके लिए इसे कई सख्त शर्तों को मानना पड़ेगा। पहले से ही देखा जाये, तो सऊदी अरब द्वारा पहले से ही 6 अरब डॉलर देने का वादा किया जा चुका है और अभी हाल ही में एमबीएस ने पाकिस्तान में सऊदी निवेश में 20 अरब डॉलर का और वादा किया है।

मकरान तट पर ग्वादर में एक तेल रिफाइनरी के निर्माण में निवेश के लिए एक बड़ा हिस्सा रखा गया है, जिसे चीन द्वारा एक रणनीतिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की योजना में प्रमुखता से शामिल है।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस रणनीतिक और आर्थिक साँठगाँठ के संदर्भ में, नई दिल्ली द्वारा इन सब पर विश्वास करना एक तरह से नासमझी होगी। भारत को सऊदी अरब के साथ राजनीतिक-रणनीतिक क्षेत्र में रियाद पर ज्यादा उम्मीद करने के बजाय भारत के आर्थिक संबंधों में होने वाले किसी भी लाभ पर ध्यान देना चाहिए।

GS World टीम...

भारत और सऊदी अरब संबंध

चर्चा में क्यों?

- सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दो दिनों की भारत यात्रा पर हैं, जिस दौरान भारत, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा।
- साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोत्तरी पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास शामिल है।
- इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच 5 एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- इस यात्रा में व्यापार व निवेश के अलावा द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की मजबूती पर विशेष फोकस किया जाएगा।

क्या हुआ समझौता?

- भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा को लेकर करार हुआ है।
- पर्यटन क्षेत्र में भारत-सऊदी अरब के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए करार हुए हैं।
- प्रसार भारती और सऊदी अरब के बीच प्रसारण साझा करने पर भी करार किया गया है।
- इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच करार हुए हैं।

मुख्य बिंदु

- विदेश मंत्रालय के सूत्र बताते हैं प्रिंस सलमान की भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और भारत अपने सहयोगी देश सऊदी अरब का आठवां रणनीतिक साझेदार देश बनने जा रहा है।
- सऊदी अरब और भारत के बीच में 27.48 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है।
- 2016-17 की तुलना में पिछले साल इसमें दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 2017-18 के दौरान दोनों देशों के बीच 1.95 लाख करोड़ का सालाना कारोबार हो रहा था।
- सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार देश है।
- अभी भारत अपनी जरुरत का 17 फीसद तेल और 32 फीसद गैस सऊदी अरब से खरीदता है।
- दोनों देश खाद्य सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त गठजोड़ बढ़ाने को इच्छुक हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. सऊदी अरामको एवं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की संयुक्त भागीदारी से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा।
   2. पाकिस्तान का ग्वादर बन्दरगाह मकरान तट पर स्थित है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements-**

   1. An Integrated refinery and petrochemical complex is being developed in Ratnagiri, Maharashtra by the joint partnership of Saudi Aramco and Abu Dhabi National Oil company.
   2. Gwadar port of Pakistan is situated on the Makran coast.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है? विश्लेषण कीजिए।

Q. What type of role could be played by Saudi Arabia to resolve the tension originated between India and Pakistan. Analyze.

(250 Words)

नोट : 19 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

World Committed To Excellence